Media Coverage of the National Conference of State Agriculture and Horticulture Ministers on 14.07.2022 at Bangalore in Karnataka

1018 एफपीओ को 37 करोड़ रु. से ज्यादा का इक्विटी अनुदान जारी

प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) का शुभारंभ, ई-नाम की कॉफी टेबल बुक का विमोचन, केंद्रीय कृषि मंत्री, रसायन व उर्वरक मंत्री एवं कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आतिथ्य में आयोजन

बेंगलुरू/नई दिल्ली,। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार/National Agriculture Market (ई-नाम) के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) का शुभारंभ किया। साथ ही, लगभग साढ़े 3 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनके 1018 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 37 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर के साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डा. मनसुख मांडविया, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी व सुश्री शोभा करंदलाजे, कर्नाटक के कृषि मंत्री श्री बी.सी. पाटिल, राज्यों के मंत्री, केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा व संयुक्त सचिव सुश्री विजयलक्ष्मी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

पीओपी की शुरूआत होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीददारों, सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार के उद्देश्य से व्यापार लेन-देन में पारदर्शिता आएगी। पीओपी पर विभिन्न

मूल्य श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, परख, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफार्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है। पीओपी से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।

ई-नाम ÷प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स÷ के रूप में सेवा प्रदाताओं के मंच का एकीकरण करता है, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता (सेवा प्रदाता जो कृषि उपज के व्यापार के लिए समग्र सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें गुणवत्ता परख, व्यापार, भुगतान प्रणाली और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सेवाएं शामिल हैं), लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता परख सेवा प्रदाता, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सेवा प्रदाता, भंडारण सुविधा सेवा प्रदाता, कृषि आदान सेवा प्रदाता, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्त व बीमा सेवा प्रदाता, सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएं, फसल अनुमान, मौसम अद्यतन, किसानों के लिए क्षमता निर्माण आदि), अन्य प्लेटफार्म (ई-कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय कृषि-व्यापार प्लेटफॉर्म, वस्तु विनिमय, निजी बाजार प्लेटफॉर्म आदि) शामिल हैं।

विभिन्न सेवा प्रदाताओं के शामिल होने से न केवल ई-नाम प्लेटफॉर्म के मूल्य में वृद्धि होती है, बल्कि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त करने के विकल्प मिलते हैं। यह किसानों, एफपीओ, व्यापारियों व अन्य हितधारकों को एकल खिड़की के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे हितधारकों के पास अधिक विकल्प होते हैं। इसके अलावा, अच्छी कोटि की वस्तु/सेवा प्रदाता का चयन करते समय, हितधारकों का समय और श्रम कम लगता है। पीओपी तक ई-नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

श्री तोमर ने 10 हजार एफपीओ के गठन के लिए सीएसएस के तहत 1018 एफपीओ को 37 करोड़ रु. से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया, जिससे लगभग साढ़े 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार से समान इक्विटी अनुदान द्वारा अनुपूरित निर्माता सदस्यों की इक्विटी से एफपीओ का वित्तीय आधार सुदृढ़ होगा और उन्हें अपनी परियोजनाओं एवं व्यवसाय विकास हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में मदद मिलेगी। योजना के तहत एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, प्रति एफपीओ 15 लाख रु. की सीमा के साथ एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य के लिए 2 हजार रु. तक के समतुल्य अनुदान व पात्र ऋणदाता संस्थान से प्रति एफपीओ के लिए 2 करोड़ रु. के परियोजना ऋण तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान है ताकि संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित हो सके।

कृषि मंत्री द्वारा विमोचित ÷कॉफी टेबल बुक÷ नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश में कृषि उत्पादों के व्यापार में पारदर्शिता व दक्षता लाने में ई-नाम के प्रयास और यात्रा को प्रदर्शित करती है। ई-नाम पर कॉफी टेबल बुक एपीएमसी मंडियों के डिजिटलीकरण की सुविधा द्वारा किसानों और हितधारकों के लाभों तथा सफलता को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है।

1018 एफपीओ को 37 करोड़ रु. से ज्यादा का इक्विटी अनुदान जारी

केंद्रीय कृषि मंत्री, रसायन व उर्वरक मंत्री एवं कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आतिथ्य में आयोजन

बेंगलुरू/नई दिल्ली ● एजेंसी

प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) का शुभारंभ, ई–नाम की कॉफी टेबल बुक का विमोचन

कर्नाटक के बेंगलुरु में आज राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार/National Agriculture Market (ई-नाम) के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) का शुभारंभ किया। साथ ही, लगभग साढ़े 3 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनके 1018 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 37 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर के साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डा. मनसुख मांडविया, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी व सुश्री शोभा करंदलाजे, कर्नाटक के कृषि मंत्री श्री बी.सी. पाटिल, राज्यों के मंत्री, केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा व संयुक्त सचिव सुश्री विजयलक्ष्मी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

पीओपी की शुरूआत होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीददारों, सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार के उद्देश्य से व्यापार लेन-देन में पारदर्शिता आएगी। पीओपी पर विभिन्न मूल्य श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, परख, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफार्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है। पीओपी से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।

ई-नाम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स के रूप में सेवा प्रदाताओं के मंच का एकीकरण करता है, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता (सेवा प्रदाता जो कृषि उपज के व्यापार के लिए समग्र सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें गुणवत्ता परख, व्यापार, भुगतान प्रणाली और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सेवाएं शामिल हैं), लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता परख सेवा प्रदाता, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सेवा प्रदाता, भंडारण सुविधा सेवा प्रदाता, कृषि आदान सेवा प्रदाता, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्त व बीमा सेवा प्रदाता, सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएं, फसल अनुमान, मौसम अद्यतन, किसानों के लिए क्षमता निर्माण आदि), अन्य प्लेटफार्म (ई-कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय कृषि-व्यापार प्लेटफॉर्म, वस्तु विनिमय, निजी बाजार प्लेटफॉर्म आदि) शामिल हैं। विभिन्न सेवा प्रदाताओं के शामिल होने से न केवल ई-नाम प्लेटफॉर्म के मूल्य में वृद्धि होती है, बल्कि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त करने के विकल्प मिलते हैं।

1018 एफपीओ को 37 करोड़ रु. से ज्यादा का इक्विटी अनुदान जारी

केंद्रीय कृषि मंत्री, रसायन व उर्वरक मंत्री एवं कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आतिथ्य में आयोजन

प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्मस (पीओपी) का शुभारंभ, ई-नाम की कॉफी टेबल बुक का विमोचन

बेंगलुरू/नई दिल्ली ● दैनिक अर्जुन सम्राट

कर्नाटक के बेंगलुरु में आज राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार/National Agriculture Market (ई-नाम) के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) का शुभारंभ किया। साथ ही, लगभग साढ़े 3 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनके 1018 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 37 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर के साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डा. मनसुख मांडविया, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी व सुश्री शोभा करंदलाजे, कर्नाटक के कृषि मंत्री श्री बी.सी. पाटिल, राज्यों के मंत्री, केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा व संयुक्त सचिव सुश्री विजयलक्ष्मी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

पीओपी की शुरूआत होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीददारों, सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार के उद्देश्य से व्यापार लेन-देन में पारदर्शिता आएगी। पीओपी पर विभिन्न मूल्य श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, परख, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफार्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है। पीओपी से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। ई-नाम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स के रूप में सेवा प्रदाताओं के मंच का एकीकरण करता है, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता (सेवा प्रदाता जो कृषि उपज के व्यापार के लिए समग्र सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें गुणवत्ता परख, व्यापार, भुगतान प्रणाली और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सेवाएं शामिल हैं), लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता परख सेवा प्रदाता, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सेवा प्रदाता, भंडारण सुविधा सेवा प्रदाता, कृषि आदान सेवा प्रदाता, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्त व बीमा सेवा प्रदाता, सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएं, फसल अनुमान, मौसम अद्यतन, किसानों के लिए क्षमता निर्माण आदि), अन्य प्लेटफार्म (ई-कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय कृषि-व्यापार प्लेटफॉर्म, वस्तु विनिमय, निजी बाजार प्लेटफॉर्म आदि) शामिल हैं। विभिन्न सेवा प्रदाताओं के शामिल होने से न केवल ई-नाम प्लेटफॉर्म के मूल्य में वृद्धि होती है, बल्कि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त करने के विकल्प मिलते हैं। यह किसानों, एफपीओ, व्यापारियों व अन्य हितधारकों को एकल खिड़की के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे हितधारकों के पास अधिक विकल्प होते हैं। इसके अलावा, अच्छी कोटि की वस्तु/सेवा प्रदाता का चयन करते समय, हितधारकों का समय और श्रम कम लगता है। पीओपी तक ई-नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।श्री तोमर ने 10 हजार एफपीओ के गठन के लिए सीएसएस के तहत 1018 एफपीओ को 37 करोड़ रु. से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया, जिससे लगभग साढ़े 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार से समान इक्विटी अनुदान द्वारा अनुपूरित निर्माता सदस्यों की इक्विटी से एफपीओ का वित्तीय आधार सुदृढ़ होगा और उन्हें अपनी परियोजनाओं एवं व्यवसाय विकास हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में मदद मिलेगी। योजना के तहत एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

1018 एफपीओ को 37 करोड़ रु. से ज्यादा का इक्विटी अनुदान जारी

प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) का शुभारंभ, ई-नाम की कॉफी टेबल बुक का विमोचन

केंद्रीय कृषि मंत्री, रसायन व उर्वरक मंत्री एवं कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आतिथ्य में आयोजन

बेंगलुरू/नई दिल्ली। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार/National Agriculture Market (ई-नाम) के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) का शुभारंभ किया। साथ ही, लगभग साढ़े 3 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनके 1018 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 37 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर के साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डा. मनसुख मांडविया, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी व सुश्री शोभा करंदलाजे, कर्नाटक के कृषि मंत्री श्री बी.सी. पाटिल, राज्यों के मंत्री, केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा व संयुक्त सचिव सुश्री विजयलक्ष्मी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पीओपी की शुरूआत होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीददारों, सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार के उद्देश्य से व्यापार लेन-देन में पारदर्शिता आएगी। पीओपी पर विभिन्न मूल्य श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, परख, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफार्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है। पीओपी से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।

ई-नाम "प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स" के रूप में सेवा प्रदाताओं के मंच का एकीकरण करता है, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता (सेवा प्रदाता जो कृषि उपज के व्यापार के लिए समग्र सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें गुणवत्ता परख, व्यापार, भुगतान प्रणाली और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सेवाएं शामिल हैं), लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता परख सेवा प्रदाता, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सेवा प्रदाता, भंडारण सुविधा सेवा प्रदाता, कृषि आदान सेवा प्रदाता, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्त व बीमा सेवा प्रदाता, सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएं, फसल अनुमान, मौसम अद्यतन, किसानों के लिए क्षमता निर्माण आदि), अन्य प्लेटफार्म (ई-कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय कृषि-व्यापार प्लेटफॉर्म, वस्तु विनिमय, निजी बाजार प्लेटफॉर्म आदि) शामिल हैं।

विभिन्न सेवा प्रदाताओं के शामिल होने से न केवल ई-नाम प्लेटफॉर्म के मूल्य में वृद्धि होती है, बल्कि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त करने के विकल्प मिलते हैं। यह किसानों, एफपीओ, व्यापारियों व अन्य हितधारकों को एकल खिड़की के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे हितधारकों के पास अधिक विकल्प होते हैं। इसके अलावा, अच्छी कोटि की वस्तु/सेवा प्रदाता का चयन करते समय, हितधारकों का समय और श्रम कम लगता है।

पीओपी तक ई-नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। श्री तोमर ने 10 हजार एफपीओ के गठन के लिए सीएसएस के तहत 1018 एफपीओ को 37 करोड़ रु. से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया, जिससे लगभग साढ़े 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

केंद्र सरकार से समान इक्विटी अनुदान द्वारा अनुपूरित निर्माता सदस्यों की इक्विटी से एफपीओ का वित्तीय आधार सुदृढ़ होगा और उन्हें अपनी परियोजनाओं एवं व्यवसाय विकास हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में मदद मिलेगी। योजना के तहत एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, प्रति एफपीओ 15 लाख रु. की सीमा के साथ एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य के लिए 2 हजार रु. तक के समतुल्य अनुदान व पात्र ऋणदाता संस्थान से प्रति एफपीओ के लिए 2 करोड़ रु. के परियोजना ऋण तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान है ताकि संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित हो सके। कृषि मंत्री द्वारा विमोचित -कॉफी टेबल बुक नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश में कृषि उत्पादों के व्यापार में पारदर्शिता व दक्षता लाने में ई-नाम के प्रयास और यात्रा को प्रदर्शित करती है। ई-नाम पर कॉफी टेबल बुक एपीएमसी मंडियों के डिजिटलीकरण की सुविधा द्वारा किसानों और हितधारकों के लाभों तथा सफलता को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है।

1018 एफपीओ को 37 करोड़ रुपए से ज्यादा का इक्विटी अनुदान जारी

● प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) का शुभारंभ, ई-नाम की कॉफी टेबल बुक का विमोचन

प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) का शुभारंभ करते केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, साथ हैं अन्य।

बेंगलुरू/नई दिल्ली, 14 जुलाई : कर्नाटक के बेंगलुरु में आज राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार(ई-नाम)के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) का शुभारंभ किया। साथ ही, लगभग साढ़े 3 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनके1018 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया। पीओपी की शुरूआत होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीदारों, सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजीटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार के उद्देश्य से व्यापार लेन-देन में पारदर्शिता आएगी। पीओपी पर विभिन्न मूल्य श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, परख, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफार्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है। पीओपी से डिजीटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। ई-नाम 'प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स' के रूप में सेवा प्रदाताओं के मंच का एकीकरण करता है, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता (सेवा प्रदाता जो कृषि उपज के व्यापार के लिए समग्र सेवाएं प्रदान करते हैं), लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता परख, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग, भंडारण सुविधा, कृषि आदान, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्त व बीमा, सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएं, फसल अनुमान, मौसम अद्यतन, किसानों के लिए क्षमता निर्माण आदि), अन्य प्लेटफार्म(ई-कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय कृषि-व्यापार, वस्तु विनिमय, निजी बाजार आदि) शामिल हैं। विभिन्न सेवा प्रदाताओं के शामिल होने से न केवल ई-नाम प्लेटफॉर्म के मूल्य में वृद्धि होती है, बल्कि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त करने के विकल्प मिलते हैं। पीओपी तक ई-नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तोमर ने 10 हजार एफपीओ के गठन के लिए सीएसएस के तहत 1018 एफपीओ को 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया, जिससे लगभग साढ़े 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार से समान इक्विटी अनुदान द्वारा अनुपूरित निर्माता सदस्यों की इक्विटी से एफपीओ का वित्तीय आधार सुदृढ़ होगा और उन्हें पूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में मदद मिलेगी। योजना के तहत एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, प्रति एफपीओ 15 लाख रुपए की सीमा के साथ एफपीओ के हर किसान सदस्य के लिए 2 हजार रुपए तक के समतुल्य अनुदान व पात्र ऋणदाता संस्थान से प्रति एफपीओ के लिए 2 करोड़ रुपए के परियोजना ऋण तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान है। कृषि मंत्री द्वारा विमोचित 'कॉफी टेबल बुक' नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश में कृषि उत्पादों के व्यापार में पारदर्शिता व दक्षता लाने में ई-नाम के प्रयास और यात्रा को प्रदर्शित करती है।

ऋण वसूली ट्रिब्यूनल-II, दिल्ली के समक्ष
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001
ओ.ए. नं. 457/2020 तिथि : 30.06.2022
केनरा बैंक ....(आवेदक)
बनाम
एमडी. अफाक आलम एवं अन्य
..........(रेस्पोंडेंट)
को,
डिफेंडेंट्स
1. मोहम्मद अफाक आलम पुत्र मोहम्मद कुदुस ...
...नगर नई दिल्ली-110009
... गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
2. ... सैक्टर-63, नोएडा-201301 (यूपी)
... गाजियाबाद, यूपी 201001
चूंकि उपरोक्त नामित आवेदक ( ) ने आपके खिलाफ रु. 36,46,881/- (रुपए छत्तीस लाख छयालीस हजार आठ सौ इक्यासी मात्र) की वसूली के लिए एक केस शुरू किया है ... यह नोटिस इस ट्रिब्यूनल में आपको 30.08.2022 को सुबह 10:30 बजे उपस्थित होने का निर्देश ...

New services under e-NAM to help farmers access more markets

Tomar launches Platform-of-Platforms that widens the ambit of e-NAM

OUR BUREAU

Bengaluru, July 14

Union Agriculture Minister, Narendra Tomar, unveiled the Platform-of-Platforms (PoP) under the National Agriculture Market (e-NAM), which will help enhance farmers' digital accessibility to multiple services and markets.

Under the new initiative, services such as assaying, storage, warehousing, sorting and grading among others will be provided through e-NAM. The e-NAM as PoP will pave way for creation of an efficient and effective "One Nation, One Market" ecosystem. Tomar said the Centre is working to improve e-NAM project further. About 1,000 APMC markets have, so far, been linked with e-NAM project, where the value of transactions has crossed ₹1.5 lakh crore, he said.

Narendra Singh Tomar, Union Agriculture Minister

Focus on 'digital agriculture'

Addressing the two-day National Conference of Agriculture and Horticulture Ministers in Bengaluru, Tomar said the government wants to promote "digital" agriculture so that farmers do not have to go to the market and depend upon middlemen. In this regard, he stressed the role of technology to track agricultural produce grown on a particular field. "In the event of loss of crop due to calamities, we can instantly provide the compensation, if we create a database of crops in a particular field," he said. Further, Tomar also called upon the State ministers to promote natural farming.

At the two day conference, around 11 critical themes ranging from the release of funds, digital agriculture, natural farming, PMFBY, marketing, horticulture, innovations in fertiliser supply, PM Kisan saturation and International Year of Millets, Agriculture Infrastructure Fund, innovation in new technologies by ICAR are being discussed by the State and Central ministers and officials concerned.

1018 एफपीओ को 37 करोड़ रु.से ज्यादा का इक्विटी अनुदान जारी: नरेन्द्र सिंह

– प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) का शुभारंभ, ई–नाम की कॉफी टेबल बुक का विमोचन

– केंद्रीय कृषि मंत्री, रसायन व उर्वरक मंत्री एवं कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आतिथ्य में आयोजन

–हिन्दुस्तान एक्सप्रेस न्यूज–

बेंगलुरू/नई दिल्ली। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर परकेंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार/National Agriculture Market (ई-नाम)के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) का शुभारंभ किया। साथ ही, लगभग साढ़े 3 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनके1018 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 37 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर के साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी व सुश्री शोभा करंदलाजे, कर्नाटक केकृषि मंत्री बी.सी. पाटिल, राज्यों के मंत्री, केंद्रीय कृषि सचिव मनोज अहूजा व संयुक्त सचिव सुश्री विजयलक्ष्मी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

पीओपी की शुरूआत होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीददारों, सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार के उद्देश्य से व्यापार लेन-देन में पारदर्शिता आएगी। पीओपी पर विभिन्न मूल्य श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, परख, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफार्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है। पीओपी से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।

ई-नाम 'प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स' के रूप में सेवा प्रदाताओं के मंच का एकीकरण करता है, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता (सेवा प्रदाता जो कृषि उपज के व्यापार के लिए समग्र सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें गुणवत्ता परख, व्यापार, भुगतान प्रणाली और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सेवाएं शामिल हैं), लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता परख सेवा प्रदाता, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सेवा प्रदाता, भंडारण सुविधा सेवा प्रदाता, कृषि आदान सेवा प्रदाता, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्त व बीमा सेवा प्रदाता, सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएं, फसल अनुमान, मौसम अद्यतन, किसानों के लिए क्षमता निर्माण आदि), अन्य प्लेटफार्म(ई-कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय कृषि-व्यापार प्लेटफॉर्म, वस्तु विनिमय, निजी बाजार प्लेटफॉर्म आदि) शामिल हैं।

विभिन्न सेवा प्रदाताओं के शामिल होने से न केवल ई-नाम प्लेटफॉर्म के मूल्य में वृद्धि होती है, बल्कि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त करने के विकल्प मिलते हैं। यह किसानों, एफपीओ, व्यापारियों व अन्य हितधारकों को एकल खिड़की के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे हितधारकों के पास अधिक विकल्प होते हैं। इसके अलावा, अच्छी कोटि की वस्तु/सेवा प्रदाता का चयन करते

शेष पृष्ठ 2 पर...

17.6 MILLION FARMERS TO BENEFIT

Govt links e-NAM platform to pvt agri-services providers

41 entities to help farmers sell their produce

SANDIP DAS
New Delhi, July 14

THE GOVERNMENT ON Thursday announced integration of trading, transportation, logistics, warehousing, assaying, packaging, weather forecast and fintech services provided by 41 private entities with its electronic National Agriculture Market (e-NAM), a move that would make more farmers use the online platform to sell their produce to buyers of their choice.

More than 17.6 million registered farmers, farmer producer organisations (FPOs), traders, commission agents and other stakeholders registered with the eNAM platform can avail these services provided by these private enterprises.

Entities whose digital platforms which have been integrated with eNAM include Star Agrobazaar Technology, Kisan Network, FPO Bazaar, Arya collateral, Aryadhan, Intello Lab, Bijak and Warehousing Development Regulatory Authority.

Agriculture minister Narendra Singh Tomar formally launched the e-NAM platform-of-platforms by stating that this would give a boost to online trade and ensure better price discovery by the platform.

According to an official with Small Farmers' Agri-Business Consortium (SFAC), which operates the eNAM, the aim behind this integration of platforms by private players under e-NAM is to make available end-to-end services to farmers along with providing a platform for price discovery.

The official said that SFAC is aiming at bringing on board as many players so that farmers have the choice to take agri-services after registering with e-NAM portal.

"Integration of our embedded fintech platform with eNAM will enable access to finance for historically excluded small farmers and strengthen them socioeconomically," Prasanna Rao, co-founder and CEO, Arya.ag, an agri-fintech platform, told *FE*.

Currently, 1,000 mandis in 22 states and Union territories are integrated into the e-NAM platform, which was launched in April 2016. At present, 17.3 million farmers, 2100 FPOs, 0226 million traders and around 0.1 million commission agents are registered with e-NAM.

However only 586 mandis are currently providing online trading services to farmers mostly within the states. Interstate trade in farm produce — a facility for a farmer in one state to sell his produce to buyers in another state — is yet to gather momentum. This is one of the chief objectives of this platform for price discovery.

Because of small land holding of the farmers, SFAC has been focussing on formation of FPOs and encouraging them participate in the e-NAM platform for collective bargaining power. SFAC launched FPO trading module during covid-19 restrictions to enable FPOs to upload their produce from collection centres, farm gate with picture and quality parameter for online bidding, without physically bringing their produce to the mandis.

Meanwhile, SFAC has empaneled private banks such as Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, HDFC Bank, Indusind Bank and ICICI Bank for provisioning of payment and settlement services for e-NAM transactions.

The empanelment of these banks enables collections and settlement of funds to various e-NAM registered beneficiaries across the country.